



Neutral Citation No. - 2026:AHC:60240-DB

ए.एफ.आर.

सुरक्षित: 11.02.2026

निणीत: 24.03.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 5496/2026

राकेश कुमार और एक अन्ययाची(गण)

बनाम

भारत संघ और 3 अन्यप्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : जगन्नाथ सिंह, सुरेंद्र नाथ सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई., अक्षत जायसवाल, आशीष कुमार मिश्रा

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति श्री अजीत कुमार,

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी,

(माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी द्वारा सुनाया गया)

1. याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री जगन्नाथ सिंह और भारत संघ के विद्वान अधिवक्ता आशीष कुमार मिश्रा की बातें सुनीं।

2. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका के ज़रिए, याचिकाकर्ता अपने खिलाफ़ शुरू की गई और जारी वसूली की कार्यवाही को चुनौती दे रहा है। साथ ही, उसने 13.11.2025 के मांग पत्र और ऋण की वसूली के संबंध में प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अधिनियम, 2002 के अध्याय III के तहत शुरू की गई वसूली की सभी संबंधित कार्यवाहियों को रद्द करने की मांग की है।

3. अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों के अनुसार, इस मामले के मुख्य तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता संख्या 1 ने अपना व्यापार बढ़ाने और कार्यशील पूंजी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिवादी संख्या 4, यानी 'सेव फाइनेंशियल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड' से दो अलग-अलग ऋण लिए थे। ये ऋण क्रमशः 4,50,000 रुपये और 8,80,000 रुपये की राशि के लिए 12.12.2018 और 21.12.2018 की मंजूरी पत्र के ज़रिए मंजूर किए गए थे। इन ऋण सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए, याचिकाकर्ता ने बोध विहार, चक्कीपाट, छिपीटोला रोड, आगरा में स्थित म्युनिसिपल संख्या 25/269 वाली अचल संपत्ति पर सुरक्षित हित बनाया है। इसके लिए उन्होंने स्वामित्व के दस्तावेज़ जमा किए हैं, जिनमें 14.01.1998 की मूल बिक्री विलेख भी शामिल है।

4. प्रतिवादी-कंपनी ने 30.07.2019 और 23.01.2020 की तारीख वाले कंप्यूटर-जनरेटेड ऋण भूगतान अनुसूची जारी किए, जिनमें ऋण की रकम मिलने और उसे चुकाने का तरीका बताया गया था।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



याचिकाकर्ता ने शुरू में तो इनका पालन किया, लेकिन बाद में ऋण खाता में भूगतान में चूक हुई। लगातार भूगतान में चूक होने के कारण, याचिकाकर्ता के ऋण अकाउंट्स को 'गैर-निष्पादीत परिसंपत्ति' (जिसे आगे 'एनपीए' कहा जाएगा) के तौर पर वर्गीकृत कर दिया गया।

5. याचिकाकर्ता का खाता एनपीए होने के बाद, प्रतिवादी संख्या 3 और 4 ने 13.08.2025 को एक नोटिस जारी किया। इसके बाद, उन्होंने 'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ़ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अधिनियम, 2002' (जिसे आगे "सरफेसी अधिनियम" कहा गया है) की धारा 13(2) के तहत 13.11.2025 को एक मांग पत्र जारी किया, जिसमें 22,33,573.73 रुपये की बकाया राशि की मांग की गई थी। उस नोटिस में यह भी बताया गया था कि केंद्र सरकार द्वारा 12.02.2021 को जारी अधिसूचना के तहत प्रतिवादी-कंपनी को एक वित्तीय संस्थान के तौर पर अधिकृत किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा मांग पत्र का पालन न करने पर, प्रतिवादियों ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत 15.01.2026 को कब्जे का नोटिस जारी किया और इस तरह सुरक्षित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्य रूप से अधिकार-क्षेत्र न होने के आधार पर विवादित कार्यवाही को चुनौती दी। यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी संख्या 4, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 2(1)(एम)(iv) के तहत बताई गई "वित्तीय संस्थान" की परिभाषा में नहीं आता है। यह भी तर्क दिया गया कि प्रतिवादियों द्वारा जिस सरकारी अधिसूचना दिनांक 12.02.2021, का हवाला दिया गया था, उसमें 'सेव फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' शामिल नहीं थी, और इसलिए सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करना ही कानूनी अधिकार के बिना था। इस तर्क के समर्थन में, 05.08.2016 की पिछली सरकारी अधिसूचना का भी सहारा लिया गया।

7. इसके अलावा यह भी कहा गया कि प्रतिवादी के पक्ष में बनाया गया सुरक्षित हित, भारत की 'सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ़ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट' (सरसाई) के पास पंजीकृत नहीं कराया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने 26.01.2026 के एक ऑनलाइन सर्च रिज़ल्ट की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि ऐसा कोई पंजीकरण मौजूद नहीं था। इसलिए यह तर्क दिया गया कि सरफेसी अधिनियम की धारा 26-डी में दिए गए कानूनी प्रावधानों को देखते हुए, प्रतिवादी याचिकाकर्ता के खिलाफ अधिनियम के अध्याय III के तहत कोई भी प्रवर्तन अधिकार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे।

8. याचिकाकर्ता की दलील का एक और पहलू ऋण से जुड़े दस्तावेजों की स्वीकार्यता से संबंधित था। यह तर्क दिया गया कि इंडियन स्टैम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-बी के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 40(बी) के अनुसार ऋण समझौतों पर पर्याप्त स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगाई गई थी और नतीजतन, उक्त अधिनियम की धारा 35 को देखते हुए, उन्हें सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता और वसूली की कार्यवाही को सही ठहराने के लिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता संख्या 2 के सह-उधारकर्ता होने की स्थिति और सुरक्षित संपत्ति के विवरण में विसंगतियों के संबंध में धोखाधड़ी के आरोप भी लगाए और उन्होंने तर्क दिया कि पूरी वसूली कार्यवाही धोखाधड़ी और प्रक्रियात्मक अवैधता से दूषित थी।

9. इसके उलट, प्रतिवादी की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका की पोषणीयता का विरोध किया और याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती दी गई कार्यवाही का समर्थन किया। यह तर्क दिया गया कि कर्ज और भूगतान में चूक की बात मानी गई है और अभिलेख से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने स्वेच्छा से ऋण की सुविधाएँ ली थीं और स्वामित्व

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



विलेख जमा करके एक वैध सुरक्षित हित बनाया था, जिससे प्रतिवादी वितीय संस्थान को कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार मिले।

10. अधिकार-क्षेत्र के बारे में याचिकाकर्ता की दलील पर, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 4 केंद्र सरकार द्वारा जारी 24.02.2020 और बाद में 12.02.2021 की अधिसूचनाओं के दायरे में आता था, और इसलिए सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए सक्षम था। आगे यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने शायद 24.02.2020 की अधिसूचना पर ध्यान नहीं दिया या 12.02.2021 और 05.08.2016 की अधिसूचनाओं को गलत समझा। उन्होंने कहा कि 24.02.2020 की अधिसूचना भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना—संख्या एस.ओ. 2641(ई), दिनांक 05.08.2016—की जगह लाई गई थी, और 12.02.2021 की अधिसूचना केवल उस सीमा तक 24.02.2020 की अधिसूचना में संशोधन करने के लिए आई थी जिसके तहत कार्रवाई शुरू की जाने वाली राशि को कम किया जा सके।

11. सरसाई के साथ पंजीकरण न होने के मामले में यह तर्क दिया गया कि ऐसा पंजीकरण केवल एक प्रक्रिया थी और इससे सुरक्षित हित या उसे लागू करने के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ता था, खासकर कर्ज लेने वाले और सुरक्षित लेनदार के बीच। यह एक निर्विवाद तथ्य था कि सुरक्षित संपत्ति पर एक ऋण था जिसके लिए वितीय संस्थान द्वारा कार्रवाई शुरू की जा रही थी, और यदि कोई तथ्यात्मक शिकायत थी तो याचिकाकर्ता एक पीड़ित व्यक्ति के तौर पर ऋण वसूली न्यायाधिकरण के सामने सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत अपील कर सकता था।

12. अपर्याप्त स्टैम्पिंग, धोखाधड़ी और गड़बड़ियों के आरोपों से जुड़ी आपत्तियों पर बात करते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि धोखाधड़ी और गड़बड़ियों के आरोप अस्पष्ट और बिना किसी सबूत के थे, और इन्हें सिर्फ जायज़ बकाया राशि का भुगतान न करने के इरादे से बाद में उठाया गया था। यह तर्क दिया गया कि सुरक्षित संपत्ति बनाने में जातसाजी के दावे को साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री पेश नहीं की गई थी। स्टैम्प इयूटी से जुड़े तर्क पर बात करते हुए, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि ऐसा तर्क स्वीकृत वितीय लेन-देन से पैदा होने वाले ठोस अधिकारों को खत्म नहीं कर सकता, खासकर सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही में। यह तर्क दिया गया कि स्टैम्प इयूटी का मुद्दा सुधारा जा सकता है और इससे लेन-देन अमान्य नहीं होता, और न ही यह सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई के संबंध में ऋण वसूली न्यायाधिकरण (जिसे आगे "डीआरटी" कहा जाएगा) के अधिकार क्षेत्र को खत्म करता है, अगर कार्रवाई सुरक्षित संपत्ति के बदले लिए गए और भुगतान में चूक हुए ऋण की राशि से संबंधित हो।

13. आखिर में, प्रतिवादियों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि मौजूदा रिट याचिका सुनवाई के लायक नहीं है क्योंकि सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के पास एक असरदार वैकल्पिक उपचार मौजूद है, और सिर्फ इसी आधार पर याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए। यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एस. शोभा बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य, 2025 एसएससीऑनलाइन एसी 177 मामले में साफ तौर पर कहा था कि जहाँ सरफेसी अधिनियम के तहत एक पूरी कानूनी प्रक्रिया दी गई है, वहाँ हाई कोर्ट को आम तौर पर रिट याचिका पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मौजूदा याचिका, जो एक निजी वितीय संस्थान द्वारा शुरू की गई वसूली कार्यवाही के खिलाफ दायर की गई है और जिसमें तथ्यों से जुड़े विवादित प्रश्न शामिल हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पोषणीय नहीं है, और

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



याचिकाकर्ताओं को अधिनियम के तहत उपलब्ध कानूनी उपचार का इस्तेमाल करने के लिए भेजा जाना चाहिए था।

14. शुरुआत में ही, हमारा मानना है कि ऋण के लेन-देन और उसके बाद भूगतान में चूक की बात पर याचिकाकर्ताओं को कोई आपत्ति नहीं है, जो सवाल उठाए गए हैं, वे मुख्य रूप से कानूनी प्रकृति के हैं; इनमें प्रतिवादी के सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के अधिकार क्षेत्र और इस रिट याचिका के पोषणीय होने से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।

15. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई विरोधी दलीलों को ध्यान में रखते हुए, विचार के लिए निम्नलिखित दो तरह के सवाल उठते हैं:

"(i) क्या प्रतिवादी संख्या 4, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 2(1)(एम)(iv) के तहत 'वित्तीय संस्थान' की परिभाषा में आता है और क्या वह इसके तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए सक्षम है; और क्या उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक प्रभावी वैकल्पिक कानूनी उपचार उपलब्ध होने के बावजूद यह रिट याचिका पोषणीय है? और

(ii) क्या अधिनियम की धारा 26-डी के तहत सरसाई में सुरक्षित हित का पंजीकरण न होने से प्रतिवादियों द्वारा अपनाए गए प्रवर्तन मानक अमान्य हो जाते हैं; और क्या ऋण समझौता पर स्टाम्प ड्यूटी की कथित कमी, साथ ही धोखाधड़ी के आरोप, जिसमें याचिकाकर्ता संख्या 2 को सह-उधारकर्ता के रूप में गलत तरीके से शामिल करना और सुरक्षित संपत्ति के विवरण में विसंगतियां शामिल हैं कि वसूली की कार्यवाही को कानूनी रूप से अमान्य बनाते हैं।"

16. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पेश की गई दलीलों और बयानों पर विचार करने के बाद, यह न्यायालय ऊपर बताए गए पहले सवाल की जांच करने के लिए आगे बढ़ता है।

17. जहाँ तक मुद्दों के पहले समूह का सवाल है, यह कोर्ट सबसे पहले यह देखना उचित समझता है कि क्या प्रतिवादी संख्या 4 एक "वित्तीय संस्थान" के तौर पर योग्य है और क्या वह सरफेसी अधिनियम, 2002 के दायरे में आता है। इसके बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस रिट याचिका के पोषणीय होने के सवाल पर विचार किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, सरफेसी अधिनियम की कानूनी व्यवस्था पर ध्यान देना ज़रूरी है। इस संबंध में, इस न्यायालय ने हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2026 एसएससी ऑनलाइन आल 32, मामले में यह कहा है:

"19. एनकेजीएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम सुबीर चक्रवर्ती और अन्य (2022) 10 एसएससी 236, मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 14 की व्याख्या करते हुए अधिनियम के मकसद पर चर्चा की और इस बात पर जोर दिया कि कानून बनाने वालों का इरादा वित्तीय संस्थानों को सशक्त बनाना है। सुगम संदर्भ के लिए फैसले का संबंधित पैराग्राफ नीचे दिया गया है:

"29. 2002 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत में वित्तीय संस्थानों को वैसी ही शक्तियां देना है जैसी दूसरे देशों में उनके समकक्ष संस्थानों, यानी अंतर्राष्ट्रीय बैंकों को मिलती हैं। ऐसी ही एक विशेषता वित्तीय संस्थानों को प्रतिभूतियों का कब्ज़ा लेने और उन्हें बेचने के लिए सशक्त बनाना है। इसे 2002 के अधिनियम के अध्याय III के तहत प्रावधानों में समाविष्ट किया गया है..."

18. इस कानून के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, खासकर इसके लागू होने और उन संस्थाओं की परिभाषा से जुड़े प्रावधानों को देखते हुए जो इसके नियमों का इस्तेमाल कर सकती हैं, यह जांचना ज़रूरी है कि क्या सरफेसी अधिनियम प्रतिवादी संख्या 4 पर लागू होता है या नहीं। इस संदर्भ में,

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अधिनियम की धारा 2(1)(एम)(iv) का जिक्र किया जा सकता है, जो केंद्र सरकार को इस अधिनियम के मकसद से कुछ संस्थाओं को "वित्तीय संस्थाओं" के तौर पर अधिसूचित करने का अधिकार देती है।

“2. परिभाषाएँ. “(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,”

(एम) “वित्तीय संस्थान” का अर्थ है”

(iv) कोई अन्य संस्थान या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-1 के खंड (एफ) में परिभाषित है जिसे केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है;”

19. सरफेसी अधिनियम, 2002 में 'वित्तीय संस्थान' की परिभाषा, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम (जिसे आगे “आरबीआई अधिनियम” कहा जाएगा) की धारा 45-1 की ओर ले जाती है। धारा 45-1, आरबीआई अधिनियम के अध्याय IIबी के अंतर्गत आती है, जिसमें जमा स्वीकार करने वाले गैर-बैंकिंग संस्थानों और वित्तीय संस्थान से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। सरफेसी अधिनियम के तहत वित्तीय संस्थान की परिभाषा को समझने के लिए, आरबीआई अधिनियम की धारा 45-1 को आसानी से समझने के लिए नीचे दिया गया है:

“45-1. परिभाषाएँ.- इस अध्याय में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(एफ) “गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी” का अर्थ है

(i) एक वित्तीय संस्थान जो एक कंपनी है;

(ii) एक गैर-बैंकिंग संस्थान जो एक कंपनी है और जिसका मुख्य व्यवसाय किसी योजना या व्यवस्था के तहत या किसी अन्य तरीके से जमा राशि प्राप्त करना, या किसी भी तरह से ऋण देना है;

(iii) ऐसा अन्य गैर-बैंकिंग संस्थान या ऐसे संस्थानों का वर्ग, जिसे बैंक केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से और आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।”

20. वित्तीय संस्थान की परिभाषा से जुड़े कानूनी प्रावधानों को पढ़ने के बाद, इस मामले में विवाद के लिए केंद्र सरकार द्वारा सरफेसी अधिनियम की धारा 2(1)(एम)(iv) के तहत जारी अधिसूचनाओं पर भी विचार करना ज़रूरी हो जाता है। इस संबंध में, याचिकाकर्ताओं द्वारा बताए गए 05.08.2016 के अधिसूचना और प्रतिवादियों द्वारा आधार बनाए गए 12.02.2021 के अधिसूचना की जांच करना ज़रूरी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या प्रतिवादी संख्या 4 अनुसूचित वित्तीय संस्थान के दायरे में आता है या नहीं। सबसे पहले, 05.08.2016 का अधिसूचना, जिस पर याचिकाकर्ता ने भरोसा किया था, नीचे दिया गया है:

“वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2016

एस.ओ. 2641(ई).—“सिक्योरिटाइज़ेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ़ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अधिनियम, 2002’ (2002 का 54) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (एम) के उप-खंड (iv) और धारा 31ए के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार उन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 'वित्तीय संस्थान' के तौर पर बताती है जो रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया अधिनियम, 1934’ (1934 का 2) की धारा 45-1 के खंड (एफ) के दायरे में आती हैं और रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ पंजीकृत हैं, और जिनकी पिछली ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार संपत्ति पाँच सौ करोड़

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



रुपये या उससे ज़्यादा है और साथ ही, जनहित में यह निर्देश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसी वित्तीय संस्थाओं पर लागू होंगे, सिवाय इसके कि धारा 13 से 19 के प्रावधान केवल उस सुरक्षित हित पर लागू होंगे जो एक करोड़ रुपये या उससे ज़्यादा मूल राशि वाले सुरक्षित ऋण की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए हासिल किया गया हो, यानी:

....”

21. ऊपर बताई गई अधिसूचना में वित्तीय संस्थानों के नाम एक टेबल के रूप में दिए गए हैं और असल बात यह है कि उस सूची में प्रतिवादी संख्या 4 का नाम नहीं है। इसके बाद 24.02.2020 की तारीख वाली अधिसूचना जारी की गई, जो इस विवाद को सुलझाने के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसे 05.08.2026 की अधिसूचना की जगह पर जारी किया गया था, इसलिए पूरी अधिसूचना नीचे दी गई है।

“वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2020

एस.ओ. 856(ई).—“सिक्योरिटाइज़ेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ़ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अधिनियम, 2002’ (2002 का 54) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (एम) के उप-खंड (iv) से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. **2641(ई) (5 अगस्त, 2016)** एस.ओ. 4176 (ई) (27 अगस्त, 2018) और एस.ओ. 5391(ई) दिनांक 24 अक्टूबर, 2018 को रद्द करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जो इन अधिसूचना के रद्द होने से पहले किए गए थे या नहीं किए गए थे, केंद्र सरकार उन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को, जिनकी परिभाषा ‘भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934’ (1934 का 2) की धारा 45-1 के खंड (एफ) में दी गई है और जिनकी संपत्ति का मूल्य 100 करोड़ रुपये या उससे ज़्यादा है, को उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के लिए ऐसे वित्तीय संस्थानों के रूप में निर्दिष्ट करती है, जो **50 लाख रुपये या उससे ज़्यादा के सुरक्षित ऋणों के मामले में प्रतिभूति हित के प्रवर्तन के लिए हकदार होंगी।**

[एफ. न. 31/52/2018-डीआरटी]

वंदिता कौल, संयुक्त सचिव।”

22. अधिसूचना को सीधे तौर पर पढ़ने से यह साफ़ है कि केंद्र सरकार ने ऊपर दिए गए अधिसूचना के ज़रिए यह तय किया है कि आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-1 के क्लॉज़ (एफ) में बताई गई सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, जिनकी संपत्ति 100 करोड़ रुपये या उससे ज़्यादा है, वे 50 लाख रुपये या उससे ज़्यादा के सुरक्षित कर्ज़ पर प्रतिभूति हित लागू करने के लिए, उस अधिनियम के उद्देश्य से वित्तीय संस्थान मानी जाएँगी, इसलिए, 24.02.2020 के अधिसूचना के बाद 05.08.2016 के अधिसूचना में प्रतिवादी संख्या 4 का नाम होना या न होना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वित्तीय संस्थान की परिभाषा के मामले में 24.02.2020 का अधिसूचना ही लागू रहता है; 12.02.2021 का अधिसूचना सिर्फ़ उस रकम के बारे में है जिसके लिए सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की जा सकती है। 12.02.2021 का अधिसूचना नीचे दिया गया है:

“वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2021

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



एस.ओ. 652(ई).—“सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ़ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (एम) के उप-खंड (iv) द्वारा मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 856 (ई), दिनांक 24 फरवरी, 2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), दिनांक 25 फरवरी, 2020 में प्रकाशित हुई थी में निम्नलिखित संशोधन करती है:— उक्त अधिसूचना में, “पचास लाख रुपये और उससे अधिक” शब्दों की जगह “बीस लाख रुपये और उससे अधिक” शब्द रखे जाएंगे। [एफ न. 31/52/2018-डीआरटी] वंदिता कौल, संयुक्त सचिव।”

23. सरफेसी अधिनियम के तहत ऊपर बताए गए कानूनी प्रावधानों और अधिसूचनाओं को देखते हुए, इसमें ज़रा भी शक नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 4 एक वित्तीय संस्थान है और इसलिए, यह अपने कानूनी ढांचे, नियमों और विनियमों के दायरे में सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों को लागू कर सकता है। इस मुद्दे पर याचिकाकर्ता की दलीलों का कोई कानूनी आधार नहीं है और इसलिए वे खारिज किए जाने योग्य हैं।

24. इस पहलू की जांच हो जाने के बाद, मौजूदा रिट याचिका के पोषणीयता के सवाल पर विचार किया जाएगा। इस संबंध में, सरफेसी अधिनियम की धारा 17 महत्वपूर्ण हो जाती है, जो अधिनियम की धारा 13(4) के तहत की गई कार्रवाई से प्रभावित किसी भी व्यक्ति को ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष एक व्यापक और प्रभावी उपचार प्रदान करती है। सरफेसी अधिनियम की धारा 17 का संबंधित हिस्सा नीचे दिया गया है:

“17. सुरक्षित ऋण की वसूली के उपायों के खिलाफ आवेदन- कोई भी व्यक्ति (जिसमें उधार लेने वाला भी शामिल है), जो इस अध्याय के तहत सुरक्षित लेनदार या उसके अधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 13 की उप-धारा (4) में बताए गए किसी भी उपचार से असंतुष्ट है, वह उस उपचार के किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर, मामले में अधिकार क्षेत्र रखने वाले ऋण वसूली न्यायाधिकरण में निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन कर सकता है:

....”

25. डीआरटी को यह जांचना होता है कि क्या सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित लेनदार द्वारा उठाए गए कदम अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बने नियमों के अनुसार हैं। अगर, जांच के बाद, न्यायाधिकरण को लगता है कि सुरक्षित लेनदार की कार्रवाई कानून के अनुसार नहीं है, तो वह उन कदमों को अमान्य घोषित कर सकता है, सुरक्षित संपत्तियों का कब्ज़ा या प्रबंधन, उधारकर्ता या पीड़ित व्यक्ति को वापस दिला सकता है, और ज़रूरी अन्य आदेश भी जारी कर सकता है। दूसरी ओर, अगर न्यायाधिकरण को लगता है कि सुरक्षित लेनदार की कार्रवाई कानूनी है, तो सुरक्षित लेनदार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षित कर्ज की वसूली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का अधिकारी होगा। इसलिए, याचिकाकर्ता के पास एक प्रभावी वैकल्पिक उपचार मौजूद है।

26. सरफेसी अधिनियम एक व्यापक कानून है जो इस मामले में उठने वाले मुद्दों और असल में इसके मुख्य उद्देश्य से जुड़े सभी मामलों से निपटता है। यह अधिनियम, धारा 18 के तहत, ऋण वसूली न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपीलिय न्यायाधिकरण में अपील करने का कानूनी उपचार भी देता है। यह एक स्थापित सिद्धांत है कि जहां कोई कानून एक असरदार वैकल्पिक उपचार देता है, वहां उच्च न्यायालय आमतौर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



इस्तेमाल करने से परहेज करेगा, सिवाय खास हालात के, जैसे कि अधिकार क्षेत्र की साफ कमी या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में इस सिद्धांत को लगातार दोहराया है।

27. इस मामले में, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने खास तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के एस. शोभा (ऊपर जिक्र किया गया), वाले फैसले का हवाला दिया है जिसमें इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निजी वित्तीय संस्थानों के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दखल देने के सीमित दायरे के बारे में कानूनी स्थिति स्पष्ट की है। इसमें की गई प्रासंगिक टिप्पणियां त्वरित संदर्भ के लिए नीचे दी गई हैं:

“8. किसी संस्था, सरकारी हो या निजी को ‘रिट अधिकार-क्षेत्र’ के दायरे में आने या न आने के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। रिट याचिका के पोषणीयता के मामले में सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी बात ‘कार्य/भूमिका, का परिक्षण होना चाहिए। अगर कोई सरकारी कर्तव्य या सरकारी कार्य शामिल है, तो उस कर्तव्य या काम से जुड़ी कोई भी संस्था, सरकारी या निजी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विशेष रिट अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत न्यायिक जांच के दायरे में आएगी।

9. हम संक्षेप में इस प्रकार कह सकते हैं:

(1) किसी कानूनी इकाई के खिलाफ रिट जारी करने के लिए, उसे राज्य का एक अंग या एजेंसी होना चाहिए, या उसे ऐसे काम सौंपे गए हों जो सरकारी हों या उनसे निकटता से जुड़े हों—जैसे कि सार्वजनिक महत्व के काम या लोगों के जीवन के लिए बुनियादी और इसलिए सरकारी प्रकृति के काम।

(2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका (i) राज्य सरकार; (ii) प्राधिकरण के विरुद्ध दायर की जा सकती है।

(iii) एक वैधानिक निकाय; (iv) राज्य का कोई अंग या एजेंसी; (v) ऐसी कंपनी जिसे राज्य से वित्त-पोषण प्राप्त हो और जो राज्य के स्वामित्व में हो;

(vi) कोई निजी संस्था जो मुख्य रूप से सरकारी कोष से चलती हो; (vii) कोई निजी संस्था जो सार्वजनिक कर्तव्य या सार्वजनिक प्रकृति की कोई ज़रूरी ज़िम्मेदारी निभा रही हो; और (viii) कोई व्यक्ति या संस्था जिस पर किसी कानून के तहत कोई कार्य करने की ज़िम्मेदारी हो, ताकि उसे वह कानूनी कार्य करने के लिए मजबूर किया जा सके।

(3) हालाँकि, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड जैसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अपने कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है, फिर भी ये दिशा निर्देश केवल निगरानी रखने और दिशा-निर्देश देने के लिए नियामक उपचार हैं, न कि कंपनी के कामकाज पर कोई दखलंदाजी या नियंत्रण।

(4) एक निजी कंपनी जो अनुसूचित बैंक के तौर पर बैंकिंग का काम कर रही है, उसे ऐसी कंपनी नहीं कहा जा सकता जो कोई सार्वजनिक कार्य या सार्वजनिक कर्तव्य निभा रही हो।

(5) आम तौर पर, परमादेश याचिका किसी सरकारी संस्था या प्राधिकरण को इसलिए जारी किया जाता है ताकि उसे किसी कानून या कानूनी नियम के तहत सौंपी गई सरकारी कर्तव्य को पूरा करने के लिए मजबूर किया जा सके। खास मामलों में, किसी निजी संस्था को भी परमादेश की रिट या परमादेश जैसी रिट जारी की जा सकती है, लेकिन ऐसा तभी किया जा सकता है जब किसी कानून या कानूनी नियम के तहत उस निजी संस्था पर कोई सरकारी कर्तव्य डाली गई हो और उसे अपनी उस सरकारी कर्तव्य को पूरा करने के लिए मजबूर करना हो।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(6) सिर्फ इसलिए कि किसी कानून या कानून जैसी ताकत रखने वाले किसी नियम के तहत किसी कंपनी या किसी अन्य संस्था को कोई खास कार्य करना जरूरी है, वह संस्था वैधानिक संस्था नहीं बन जाती।

(7) अगर कोई निजी संस्था कोई सार्वजनिक कार्य कर रही है और किसी अधिकार से वंचित किया जाना उस संस्था पर सौंपे गए सार्वजनिक ज़िम्मेदारी से जुड़ा है, तो सार्वजनिक कानून उपचार को लागू किया जा सकता है। सार्वजनिक संस्था पर डाली गई ज़िम्मेदारी कानूनी या किसी और तरह की हो सकती है और ऐसी शक्ति का स्रोत मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी, ऐसी कार्रवाई में सार्वजनिक कानून का तत्व होना चाहिए।

(8) हॉल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, तीसरा संस्करण, भाग 30, पेज 682 के अनुसार, “सार्वजनिक प्राधिकरण कोई ऐसी संस्था है, ज़रूरी नहीं कि वह काउंटी काउंसिल, नगर निगम या कोई अन्य स्थानीय प्राधिकरण ही हो, जिसे सार्वजनिक कानूनी कर्तव्य निभाने होते हैं, और जो जनता के फ़ायदे के लिए अपने कर्तव्य निभाती है और कामकाज करती है, न कि निजी मुनाफ़े के लिए।” सार्वजनिक प्राधिकरण या सार्वजनिक कार्य की कोई सामान्य परिभाषा नहीं हो सकती। हर मामले के तथ्य ही इस बात को तय करते हैं।”

28. मुद्दों के पहले समूह पर निकले निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय मुद्दों के दूसरे समूह की जांच करने से परहेज करती है, क्योंकि उन मुद्दों की जांच डीआरटी द्वारा सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 17 के तहत कार्यवाही में ठीक से की जा सकती है।

29. चूंकि यह न्यायालय मानती है कि सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिवादी संख्या 4 एक वित्तीय संस्थान है, इसलिए एक प्रभावी वैकल्पिक वैधानिक उपचार उपलब्ध होने और सुप्रीम कोर्ट के एस. शोभा (ऊपर ज़िक्र किया गया) मामले में दिए गए फैसले को देखते हुए, यह रिट याचिका पोषणीय नहीं है।

30. इसलिए, याचिका खारिज की जाती है। हालाँकि, अगर याचिकाकर्ता को वित्तीय कंपनी के खिलाफ कोई शिकायत है, तो वह कानून के अनुसार सही फोरम पर उचित कानूनी उपचार अपना सकता है, जिसमें सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत उपलब्ध कानूनी उपचार के लिए डीआरटी से संपर्क करना भी शामिल है। लागू/दण्ड के बारे में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

(न्यायमूर्ति श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी) (न्यायमूर्ति श्री अजीत कुमार)

24 मार्च, 2023

शिव

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”